Popular Front of India

+91 11 2 9949902
popularfrontmail@gmail.com
www.popularfrontindia.org
/PopularFrontofIndiaOfficial
@PFIOfficial
/PopularFront EMedia
/pfiofficial

प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली
7 फरवरी 2020

दिल्ली चुनावों के अवसर पर पॉपुलर फ्रंट के फंड और संबंधों को लेकर मीडिया की ज़बानी अपने आकाओं की कहानियां बेवज़न खबरें

केंद्रीय सचिवालय द्वारा जारी किया गया बयान

मीडिया के एक वर्ग ने अपने राजनीतिक आक़ाओं के तत्काल और लंबे फायदे की पूर्ति के लिए जो गलत बातें फैलाने का अभियान छेड़ रखा है, उसने शालीनता, निष्पक्षता, ईमानदारी और पत्रकारिता की नैतिकताओं की तमाम हदों को तोड़ दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) के हवाले से उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बदनाम करने और निशाना बनाने का जो नया सिलसिला शुरू किया है, वह दिल्ली विधानसभा चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए, मतदाताओं को प्रभावित करने की उनकी आखिरी कोशिश के सिवा कुछ नहीं है।

सभी सर्वे यह बताते हैं कि अगर बिना किसी हेरफेर के सही तरीके से चुनाव होते हैं, तो दिल्ली में बीजेपी की हार तय है। बीजेपी के पास अपने विभाजनकारी और सांप्रदायिक फार्मूले के सिवा, चुनाव में पेश करने के लिए विकास का कोई एजेंडा नहीं है। साथ ही सीएए, एनआरसी और एनपीआर का फैसला उन पर उल्टा पड़ गया है और नफरत के सौदागर संघ परिवार के फासीवादी लोगों को छोड़कर देश के सभी समझदार नागरिक देश को धार्मिक बुनियाद पर बांटने की उनकी कोशिश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।

यह लोग शाहीन बाग के आंदोलन को किसी फंडेड आतंकवादी गतिविधि की तरह पेश करके, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर भोले–भाले वोटरों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ–साथ, दिल्ली चुनावों में उनके असल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों आप पार्टी और कांग्रेस को भी बिला वजह शाहीन बाग के आंदोलन में घसीटा जा रहा है। केंद्र सरकार की ''गैर–आधिकारिक'' अधिकारी ज़बान रिपब्लिक टीवी ने अब यह आरोप फैलाना शुरू कर दिया है, कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परवेज़ अहमद के आप नेताओं के साथ संबंध हैं और वे अक्सर व्हाट्सएप से बातचीत करते रहते हैं।

पॉपुलर फ्रंट एक ऐसा संगठन है जो देश की सभी कानूनी आवश्यकताओं का पूरा पालन करता है। अधिकारियों और उनकी कठपुतली मीडिया के द्वारा समय–समय से लगाए गए विभिन्न बेबुनियाद आरोपों को छोड़कर, आज तक संगठन के खिलाफ ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ है जो कानून और देश के खिलाफ हो। पॉपुलर फ्रंट की गतिविधियां हमेशा से ही पारदर्शी रही हैं। यह कोई प्रतिबंधित संगठन नहीं है। इसके सदस्य भारत के नागरिक हैं, जिन्हें भारतीय संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकार और सुविधाएं हासिल हैं। समाज का सदस्य होने के नाते, उन्हें जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर समाज में बसने वाले दूसरे लोगों के साथ बातचीत तो करनी ही होगी। जिस तरह से भारत का कोई भी दूसरा नागरिक किसी से फोन पर बात कर सकता है, हर स्तर के लोगों से मुलाकात कर सकता है, उनसे चैट कर सकता है और मेल भेज सकता है, वगैरा–वगैरा, उसी तरह से यह लोग भी दूसरों से बातचीत कर सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी तो नहीं है। हमें यकीन है कि कोई भी समझदार व्यक्ति एक सेक्युलर लोकतांत्रिक देश के अंदर इसमें कोई गुनाह महसूस नहीं करेगा।

आर्थिक लेन–देन को लेकर लगातार अप्रमाणित आरोप लगाए जा रहे हैं, हालांकि पॉपुलर फ्रंट इस मामले पर सबूत के साथ पूरी सफाई पेश कर चुका है। ई.डी. की बातचीत और दस्तावेज़, जिन्हें राज़ रखा जाना चाहिए, रिपब्लिक टीवी बड़े गैर–ज़िम्मेदाराना तरीके से उन्हें बयान कर रहा है। वास्तव में वे ऐसा करके ई.डी. जैसी एक केंद्रीय आर्थिक जांच एजेंसी की साख को ठेस पहुंचा रहे हैं। जहां तक हमारी जानकारी है, ई.डी. ने पॉपुलर फ्रंट के लोगों के साथ अपनी सुनवाई के विवरण पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, और उनकी पुष्टि के बिना इस

तरह की बातें फैलाकर यह मीडिया सरकारी राज़ के उल्लंघन के गुनहगार है। सच्चाई यह है कि हमारे पदाधिकारियों में से किसी ने भी ई.डी. के सामने हाज़िर होने से बचने की कोशिश नहीं की है, और हम उनके साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले भी हर मौके पर दूसरी एजेंसियों के साथ भी सहयोग किया है। हमें यकीन है कि इतनी सच्चाई तो वे भी जानते होंगे।

आरएसएस समर्थित बीजेपी सरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को आतंकवादी बताकर और शाहीन बाग के आंदोलन को पॉपुलर फ्रंट से पैसा मिलने की बातें फैलाकर ऐसा रोल अदा कर रही है, जिस तरह खुद चोर भीड़ में ''पकड़ो–पकड़ो, चोर–चोर'' चिल्लाता है। वास्तव में बीजेपी ही हर तरह के गैरकानूनी तरीकों से पैसा जमा करती है। उदाहरण के तौर पर 23 नवंबर 2019 को 'बिज़नेस स्टैंडर्ड' में आई एक ख़बर के अनुसार, बीजेपी को एक ऐसी कंपनी से करोड़ों रुपए चंदा मिला है, जिसके बारे में ई.डी. यह जांच कर रही है कि उसने 1993 के मुंबई बम धमाका मामले के आरोपी इकबाल मिर्ची से कथित रूप से संपत्ति खरीदी है। ख़बर यह कहती है कि इक़बाल मैनन उर्फ इकबाल मिर्ची से आर्थिक लेन–देन और संपत्ति खरीदने में शामिल कंपनी ने 2014–15 में बीजेपी को 10 करोड़ रूपये दिए थे। मिर्ची को दाऊद इब्राहिम का करीबी माना जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बीजेपी की आतंकवादी फंडिंग सहित अन्य आर्थिक लेन–देन के मामले को नैतिकता से खाली कठपुतली मीडिया ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के अवसर पर कोई चर्चा का विषय नहीं बनाया है।

पॉपुलर फ्रंट संगठन पर लगाए गए आतंकवादी फंडिंग और पैसों के दुरुपयोग सहित सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज करता है और साथ ही एक लोकतांत्रिक एवं कानूनी तरीके से काम करने वाले संगठन को केवल सस्ती राजनीति के लिए बदनाम करने की सरकार और उसकी पक्षपाती कठपुतली मीडिया की कोशिशों की कड़ी निंदा करता है।

पॉपुलर फ्रंट एक बार फिर ऐसे सभी लोगों को चुनौती देता है कि वे सत्ता, मशीनरी और मीडिया का इस्तेमाल करके झूठी बातें और खबरें फैलाने के बजाय, सबूत के साथ आरोपों को साबित करके दिखाएं। हमें विश्वास है कि परिस्थितियों पर नज़र रखने वाले दिल्ली के ज़िम्मेदार वोटर मीडिया की बेवज़न ख़बरों को राजनीतिक इतिहास के कूड़ेदान में डाल देंगे।

डॉ मोहम्मद शमून
डायरेक्टर, जनसंपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
नई दिल्ली